if some misconceptions have crept in, whoever may be responsible for it, they must be cleared.

MR. CHAIRMAN: Question No. 189.

Sugar distribution policy

£189. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:†
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have lately introduced a modified sugar distribution policy; and

(b) if so, the details of the policy underlining the main modifications and features thereof, giving reasons for such modifications?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) 1992–93 एवं 1993–94 चीनी मौसमों के दौरान चीनी उत्पादन में कमी के कारण सरकार ने चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सामान्य खुले लाइसेंस के तहत चीनी आयात करने की अनुमति दी है। तदनुसार आयातित चीनी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। पत्तनों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्दिष्ट वितरण स्थानों तक इस आयातित चीनी के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गयी है। कुछ राज्यों के मामलों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आदि में आयातित चीनी को सीधे पत्तनों से उठाने की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी का निर्गम मूल्य 9.05 रुपए प्रति किलोग्राम जारी रहेगा।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Sir, may I know from the hon. Minister the total quantity of sugar imported this year through, number one, the private channels, and number two, the Gvernment and public channels? What effective steps are being taken by the Government to ensure regular flow of the commodity into the open market and the PDS so as to maintain the price level and to curb the price rise since there is ample scope for manipulation by the sugar barons, which can be used by the traders to the detriment of the consumers?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, हमारे देश में चीनी दो तरह की है–एक वह चीनी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 9 रुपए 05 पैसे किलो के हिसाब से पूरे हिन्दुस्तान के यूनियन टैरिटरी को दी जाती है और दूसरी चीनी वह है जो फ्री मार्किट में बिकती है। भारत में इस साल प्रोडक्शन कम होने के कारण हिन्दुस्तान में केवल 96 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दस लाख टन चीनी की कमी थी और फ्री मार्किट के लिए भी सरकार ने ओजियल के अन्तर्गत, ओपन जनरल मार्किट जो है, हिन्दुस्तान के किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जो चीनी बाहर से मंगाना चाहे, उसको मंगाने की इजाजत भारत सरकार ने ओजियल की नीति के अन्तर्गत दी और कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गयी कि वह फ्री मार्किट से चीनी खरीदे और बेचे।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है, उस प्रणाली को कायम रखने के लिए जो हमारे पास 10 लाख टन चीनी की कमी थी, उसको हमने एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से मंगाया है और उस चीनी को हम फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से पूरे देश को दे रहे हैं।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Sir, this change in policy did not result in a comprehensive solution to the problem and subsequently, the STC and the MMTC were also instructed to carry out the import of sugar. Accordingly, the STC and the MMTC started inviting offers and tenders for import of sugar along with others. I

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Sushil Kumar Sambhajirao Shinde.

have received a complaint that the Kerametal Company Limited of Slovakia has recently made an offer to supply 25,000 tonnes of sugar to the MMTC. It is understood that the rates, which the have offered, are not only the lowest, but almost 35 dollars to 40 dollars lower per metric ton than the supplies from the Refined Sugar Association, that is, RSA. Is the MMTC hesitating to finalise the contract only on the point that they want to make all the supplies at the port of discharge, whereas the suppliers, in accordance with the international norms, want payments after the inspection etc. by the buyers, at the loading port?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का इनका जो प्रश्न है, उससे कोई रिश्ता नहीं है । भारत सरकार का जो खाद्य मंत्रालय है, उसने ओजियल के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के प्राईवेट उद्योगपतियों को चीनी मंगाने की इजाजत दे दी है । जो जितनी चीनी चाहे, वह हिन्दुस्तान में ला सकता है और फ्री मार्किट में बेच सकता है ।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण का सवाल है, वह जिम्मेदारी, वह प्रार्थना पत्र हमने भारत सरकार को दिया और भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से यानी एम.एस.टी.सी. और एस.टी.सी. के माध्यम से चीनी को मंगाया है और किस रेट पर चीनी को मंगाया है, वाणिज्य मंत्रालय ने और क्या उनका कांट्रेक्ट सिस्टम है, यह जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्रालय की है । हमारी जिम्मेदारी क्या है..... (**व्यवधान**) मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं, वह यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीनी एम.एस.टी.सी. और एस.टी.सी. के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से मंगायी गयी है, वह चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम दे रहे है । और उसके लिए हमने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया को जिम्मेदारी दी है कि वह हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों मे चीनी लिफट करेंगे और उस को लिफ्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचायेंगे । एम.एस.टी.सी. और एस.टी.सी. वाणिज्य मंत्रालय के संगठन है । उनके माध्यम से वह चीनी विदेशों से मंगाते हैं । तो खाद्य मंत्रालय का इनसे कोई रिश्ता नहीं है ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, I would like to know whether it is a fact that it was mainly the short supply of sugar through Public Distribution System during April to June that sent the prices of sugar sky-rocketing in the open market. If so, I would like to know why regular supply of sugar to PDS was not possible these months despite a bufferstock and overflow of 30 lakh tonnes from last year. And part (b) of my question is this. I would like to know, in detail, how the release of sugar quotas for free sale is managed effectively to prevent the price-hike by such a diversion and why this system has failed this time to curb the price-rise in the case of this basic commodity despite imports.

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, माननीया सदस्या ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मुझे यह बताना है कि 9 रुपये 5 पैसे किलो के हिसाब से चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दी जाती है । वह लगातार दी जा रही है । हिन्दुस्तान के सभी राज्यों को चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, हम चीनी का कोटा 3 लाख 35 हजार टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये एलाट कर रहे हैं । अब उसमें राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 9 रुपये 5 पैसे किलो के हिसाब से चीनी बेचे ।

दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है कि चीनी की महंगाई बढ़ी है । फ्री मार्केट में जो खुले बाजार में चीनी है उसे कोका कोला बनाने वाले, पेप्सी कोला बनाने वाले, बिस्कुट बनाने वाले या बड़े धनाढ्य लोग खरीदते हैं । यह सही है कि हिन्दुस्तान में चीनी का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है । इस लिये फ्री मार्केट में स्पीकुलेटर्स, होर्डर्स और ब्लैक मार्कीटियर्स जो

भी इस तरह के लोग हैं उन लोगों ने दाम-बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन सरकार ...

श्री जगेश देसाई : चीनी का दाम कम किये हैं ? **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, मैं इनके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं । एक भी ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैंने न दिया हो तो जो आप चाहे सजा दें । ... **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय पहली बात यह जाननी चाहिये माननीय सदस्य को । अभी हमारे विद्वान माननीय सदस्य जगेस देसाई जी पूछ रहे थे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये जो कोटा रिलीज हुआ वह क्या कम हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि उस में कोई कमी नहीं हुई । आप फाइल देख सकते हैं । जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नार्मल कोटा रिलीज किया गया है उसमें एक किलो भी कम रीलीज नहीं किया गया है । जहां तक फ्री मार्केट का सवाल है, फ्री मार्केट में चीनी जो ओपन बाजार में बिकती है उसकी समस्या हल करने के लिये 15 मार्च को भारत सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस की नीति की घोषणा की और उसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना कस्टमड्यूटी दिये विदेशों से चीनी खरीदकर हिन्दुस्तान के बाजार में बेच सकता है आज हिन्दुस्तान में विदेश से चीनी आने के कारण फ्री मार्केट में चीनी का फैक्ट्री दाम सबसे कम हो गया है, 12 रुपये किलो है. . . .

SHRI K. R. JAYADEVAPPA: Sir, it is not true. . . *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over. . . *(Interruptions)*. . . Hon. Minister, the Question Hour is over.

श्री कल्पनाथ राय : नहीं, . . . **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?. . . *(Interruptions)* . . . Will you please sit down? The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Institutions granted deemed University status

*182. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the names of the institutions in the country which have the status of deemed university and the names of those institutions which have acquired such status in 1992, 1993 and so far in 1994;

(b) what are the names of the institutions which have applied for granting them tht deemed university status and which are pending with the Government; and

(c) what are the present guidelines and Memorandum of Association (MOA) rules on the subject?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) A list indicating the names of 34 institutions which have been granted the status of a deemed University is annexed as a statement-I *(See* below).

The names of institutions which acquired such status during 1992, 1993 and 1994 are given below:

1992—1. Bengal Engineering College, Howrah (W.B.)

1993—1. Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune.

2. Manipal Academy of Higher Education, Manipal.

3. Sri Chandrasekharandra Saraswathy Nyaya Shastra Mahavidyalaya, Kanchipuram.

1994—Nil

(b) The names of institutions which have applied for deemed University status and are pending with the UGC as on